







# संपादकीय अब समय आ गया और सरल कर व्यवस्था ज़खरी

# नई सहमति ज्यादा अहम

मानव सरोवर की यात्रा फिर शुरू करने और द्विपक्षीय व्यापार सुगम बनाने संबंधी सहमतियां डोवाल- वांग वार्ता का व्यावहारिक नतीजा हैं। दूरगामी नजरिए से सीमा विवाद के हल पर 2005 में तय हुई राजनीतिक कसौटियों पर नई सहमति ज्यादा अहम है। भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच सीमा विवाद के निपटारे पर बीजिंग में हुई वार्ता का सार यह है कि चार साल तक तनावपूर्ण रहने के बाद दोनों का रिश्ता अब पटरी पर लौट रहा है। भारतीय प्रतिनिधि अजित डोवाल और चीनी प्रतिनिधि वांग यी की वार्ता में, चीनी विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक, छह सूत्री सहमति बनी। भारतीय विज्ञप्ति में उन छह सूत्रों का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, लेकिन कहा गया है विदोनों विशेष प्रतिनिधियों ने आपसी रिश्ते को सकारात्मक दिशा प्रदान की है। तिब्बत के रास्ते से मानव सरोवर की यात्रा फिर शुरू करने और द्विपक्षीय व्यापार को सुगम बनाने संबंधी सहमतियां इस वार्ता का व्यावहारिक नतीजा हैं। मगर दूरगामी लिहाज से सीमा विवाद हल करने के लिए 2005 में दोनों देशों के बीच तय हुई राजनीतिक कसौटियों पर नई सहमति ज्यादा अहम है। 1988 से 2005 तक भारत- चीन संबंध सकारात्मक दिशा में थे। उसी क्रम में 2005 में बनी सहमति को एक बड़ी कामयाबी माना गया था। डोवाल- वांग वार्ता में इस पर भी जो दिया गया कि सीमा विवाद का हल पैकेज के रूप में होगा। यानी पूरब में अरुणाचल और पश्चिम में लद्धाख सीमाओं पर जो मतभेद हैं, उन पर एकमुश्त सहमति बनाई जाएगी। हर समाधान का आधार लेन-देन की भावना होती है। दोनों देश अगर इस भावना पर रजामंद हो रहे हों, तो आशा की जा सकती है कि इस लंबे विवाद का हल निकल आएगा। बहरहाल, इस रास्ते में अनेक दिक्कतें हैं। दोनों देशों की अंदरूनी राजनीतिक प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय पहलुओं का साथ भारत-चीन संबंधों पर पड़ते रहा है। इसके अलावा यह देखना होगा कि क्या सचमुच अब नए सिरे से उभर रही सहमतियों पर चीन कायम रहता है। भारत में अक्सर यह संदेह रहा है कि ऐसी सहमतियों का इस्तेमाल चीन सीमा के करीब अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए करता है। वैसे चीन से बेहतर रिश्ता दोनों देशों की आर्थिक जरूरत है जैसाकि इस वर्ष संसद में पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था। इसलिए फिलहाल चीजें पटरी पर लौट रही हैं, तो उसे एक सकारात्मक घटनाक्रम कहा जाएगा।

डा. जयंती लाल भंडारी



जुर्माना लगाया जाएगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। खास किस्म के फैटिफ़इड चावल पर जीएसटी कम किया गया है। कैंसर की जीन थेरेपी को कर मुक्त किया गया है। इस्टेमाल शुदा यानी पुराने बाहनों की बिक्री पर कर दर को 18 फीसदी कर दिया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इसी वर्ष अगस्त 2024 में आयकर अधिनियम सरल बनाने के लिए मुच्य आयकर आयुक्त वीके गुप्ता की अध्यक्षता में गठित समिति कर रियायतों को तरक्संगत बनाने, कर गणना के तरीके का स्तर बढ़ाकर इसे विश्वस्तरीय बनाने और अपील करने की व्यवस्था में जटिलता कम करने करने संबंधी सुधारों पर तेजी से काम कर रही है। यह समिति कर विशेषज्ञों और विभिन्न निकायों से प्राप्त सिपारिशों की समीक्षा कर रही है। जातव्य है कि आयकर अधिनियम 1961 की करीब 90 धाराएं अपनी प्रारंभिकता छो चुकी हैं। ये धाराएं विशेष आर्थिक क्षेत्र, दूरसंचार, पूँजीगत लाभ सहित कर छूट एवं कटौती जैसे मामलों में कारगर नहीं रह गई हैं। मौजूदा स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) व्यवस्था को सरल करने के लिए सीमा शुल्क कानून की तरह ही समिति दरों की एक व्यापक अनुसूची बनाने पर आगे बढ़ रही है। इससे कानूनी जटिलताएं और मुकदमेबाजी में काफी कमी आएगी तथा कर कटौती प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी होगी। उम्मीद है कि वीके गुप्ता समिति की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत होगी और इसके आधार पर विधि मंत्रालय की मदद से नए आयकर विधेयक का मर्सोदा तैयार किया जाएगा। निश्चित रूप से पिछले एक दशक में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में तेज सुधारों का सिलसिला लगातार बढ़ा है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। पिछले एक दशक से आयकर कानून में जो अहम सुधार किए गए हैं उससे जहां आयकरदाताओं को सुविधा मिली, वहां आयकरदाताओं की संख्या बढ़ाने में भी मदद मिली है। इन सुधारों में प्रमुख रूप से 25 सितंबर 2020 से पूरे देशभर में लागू करदाताओं के लिए पहचान रहित अपील (फेसलेस अपील) व्यवस्था और वर्ष 2019 में लागू करदाता चार्टर (टैक्सपेयर चार्टर) और पहचान रहित समीक्षा (फेसलेस असेसमेंट) जैसे बड़े आयकर सुधार प्रमुख हैं। इसके अलावा नॉन फाइलर्स, मार्निटरिंग सिस्टम (एनएमए) के जरिए ऐसे लोगों की पहचान की जाती है जिन्होंने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है, पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। पिछले 10 वर्षों में आयकर संग्रह में करीब 182 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर संग्रह लगभग चार गुना बढ़कर 10.45 लाख करोड़ रुपए का रहा। यह भी कोई छोटी बात नहीं है कि आयकर वर्ष 2023-24 में 8.09 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। साथ ही मौजूदा वित वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष से अधिक आयकर रिटर्न और अधिक आयकर प्राप्ति का परिवृद्ध्य उभरकर दिखाई दे रहा है। जिस तरह देश में आयकर संबंधी सुधारों से आयकरदाताओं की संख्या और आयकर राशि में तेजी से इजाफ़ हुआ है, उसी तरह देश

में अप्रत्यक्ष करों में ऐतिहासिक सुधार कहा जाने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार वे स्तर पर लगाने वाले 17 केंद्रीय और राज्य स्तरीय टैक्स के साथ-साथ करीब 23 अलग-अलग तरह वे उपकरणों को समाहित किया गया है। जीएसटी विनिर्माताओं, कारोबारियों, निर्यातकों और आम लोगों के लिए लाभप्रद माना गया है। जीएसटी लागू होने वे पूर्व वित्त वर्ष 2016-17 में अप्रत्यक्ष कर संग्रह (केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क आदि) से करीब 8.63 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी। जीएसटी लागू होने के बाद जीएसटी से टैक्स संग्रहण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीएसटी का संग्रहण 20.18 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पूर्ववर्ती साल के मुकाबले 11.7 फीसदी बढ़ि को दिखाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की इस अवधि के मुकाबले 9 फीसदी बढ़कर 14.56 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसमें कोई दंगत नहीं है कि दुनिया की तेज बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत बढ़ते उद्योग-कारोबार, सर्विस सेक्टर, शेयर बाजार और मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति की नई ऊँचाइयों के कारण देश में टैक्स संग्रहण में तेज बढ़ि हो रही है। वस्तुतः कर संग्रह में तेज बढ़ि से बुनियादी ढांचे, सामाजिक सेवाओं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार की क्षमता बढ़ रही है। सरकार की मुद्दियों में बढ़ता कर राजस्व न केवल

आलेख

# स्वस्थ मध्यप्रदेश-सशक्त मध्यप्रदेश को मूर्ति स्वरूप देने उठाये गए सशक्त कदम

मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। स्वस्थ मध्यप्रदेश की संकल्पना को साकार करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इससे प्रदेश के हर नागरिक को सुलभ, निशुल्क और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। प्रदेश सरकार का संकल्प है कि हर नागरिक को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और प्रदेश एक आदर्श स्वास्थ्य मॉडल के रूप में स्थापित हो। आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्यप्रदेश के निर्माण के लिये प्रदेश सरकार निरंतर अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का एकीकरण किया गया है। इस कदम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों के बीच बेहतर सम्बन्ध स्थापित हुआ है। साथ ही मरीजों को समय पर और बेहतर इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। 0-46 हजार 491 नए पदों का सूजनस्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए मानव संसाधनों में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने 100% पब्लिक हैल्थ कैडर' की शुरुआत की है। इसमें 46,491 नए पदों का सूजन किया गया है, जिन्हें अगले दो वर्षों में भरा जाएगा। इस पहल से प्रदेश के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की कमी दूर होगी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। प्रदेश में निशुल्क दिवाएं और जांच सेवाएं भी व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जिला अस्पतालों में अब 530 प्रकार का दवाएं आर 132 प्रकार का जांच सेवाएं उपलब्ध हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी 80 प्रकार की जांच सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इन प्रयासों से गरीब और जरूरतमंद मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। प्रदेश में 11,789 हैल्प्य एंड वेलनेस सेंटर्स सक्रिय किए गए हैं, जहां नागरिकों को घर के पास उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। इन सेन्टर्स से अब तक 3.62 करोड़ से अधिक दवाइयाँ वितरित की जा चुकी हैं और 2.91 करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं। इसके अलावा, टेलीमेडिसिन सेवाओं के अंतर्गत 20.47 लाख से अधिक कॉल्स के जरिए ग्रामीण इलाकों के मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह उपलब्ध कराई गई है। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी है। अब तक प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिनमें 99 लाख कार्डों का आधार द्रू-यद्वाष सत्यापन हो चुका है। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 9 लाख वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड बनाए गए हैं। यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की एक मजबूत गारंटी बन चुकी है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने में मध्यप्रदेश शीर्ष पर है। प्रदेश में पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। इससे दूर-दराज के क्षेत्रों से गंभीर मरीजों को तत्काल बढ़े अस्पतालों में पहुंचाकर जीवनरक्षक उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह सेवा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार में एक महत्वपूर्ण कदम है। चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों का विस्तार किया गया है। वर्ष-2003 तक प्रदेश में केवल 5 शासकीय मेडिकल कॉलेज थे, जो अब बढ़कर 17 हो गए हैं। एमबीबीएस सीटों की संख्या 720 से बढ़कर 2,575 हो गई है। आगामी 2 वर्षों में 8 और शासकीय मेडिकल कॉलेज बनाये जाएंगे। इसके अलावा, 12 जिलों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षा संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये सभी आवश्यक प्रबंध किये जा रहे हैं। वर्तमान में 24 शासकीय नर्सिंग कॉलेज संचालित हैं, 14 और मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश में जल्द ही 38 नर्सिंग कॉलेज हो जाएंगे। 250 पैरामेडिकल कॉलेजों में लगभग 25,000 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मेडिकल ट्रॉरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल सिटी-मेडिकल सिटी की स्थापना उज्जैन में की जा रही है।

श्रुति व्यास

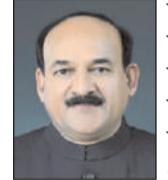
भारत को सचमुच एक खुशियों भरे भविष्य को आरे ले गए मनमोहन सिंह

भरोसा हुआ। उसने दुबारा पूछा, क्या वाकई तुम्हे गवं है? (क्या आप सचमुच?) मैंने उसकी ओर सवाल उछाला, क्या तुम्हे अपने मेक्सिकन होने पर गवं नहीं है। उसने तपाक से कहा नहीं। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। मैं सोच रही थी कि किसी को अपने देश से प्यार न हो, भला ऐसा कैसे संभव है! वह भी शायद मेरी ओर देखते हुए सोच रहा था कि इसका उलट कैसे संभव है। इसके पहले कि चर्चा आगे बढ़ती, छात्रों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। हम दोनों अपने-अपने समूहों से घिर गए और बातचीत यहीं समाप्त हो गई। इसके बाद कभी वह अधूरी चर्चा पूरी न हो सकी। लेकिन मेरे मन में हमेशा सवाल कौंधता रहा कि उसके मन में ऐसा सवाल क्यों आया? जब मैं स्काटलैंड गई थी तब भारत दूर गति से फल-फूल रहा था जबकि ब्रिटेन मंदी में डूब-उत्तर रहा था। जैसा कि मैंने विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदनों में %अपने वक्तव्य' में कहा था, भारत बदलाव के कागार और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इसमें तब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। हमारा शेयर बाजार तेजी से बढ़ रहा था, व्यापार-व्यवसाय में नए प्रयोग हो रहे थे, लोकतंत्र जिंदा था और माहौल उत्साहपूर्ण था। विकसित देशों में रह रहे मेरे मित्र कहते थे, कम से कम तुम्हारे पास तो वापस जाने का विकल्प है ही। भारत में आसानी से तुम्हे काम मिल जाएगा। मैं गर्वित और अच्छा फील करती थी। भारत बदल रहा था और होके व्यक्ति इसे देख और महसूस कर सकता था। जब मैं बड़ी हो रही थी तब

मा नुङ्ग कमा एसा नहा लगा। कि एसा काइ धाज ह जा मैं खो रही हूँ जो मेरे पास नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ नियम-कानून और प्रतिबंध थे, जिनका पालन हमें करना पड़ता था। मगर जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं थी। एक बच्ची बतारै मेरा जीवन उदास नहीं था। हम रोज एक घंटे कम्प्यूटर का इस्तेमाल कर सकते थे और शाम को केविल टीवी देख सकते थे, हमें स्कूल ले जाने के लिए कार थी और समय-समय पर हमें नए आधुनिक खिलौने और गेम मिल जाते थे। ये सभी उस समय भारत में आसानी से उपलब्ध थे। हम लोगों को सिनेमा भी ले जाया जाता था और छुट्टियों में हम शहर के बाहर भी जाते थे। आज जब मैं पीछे मुड़कर उस दौर को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारा बचपन खुशनुमा इसलिए था क्योंकि उस दौर में भारत और भारतीय दोनों खुश थे, फालतू की चिंताएं नहीं थी। सब आगे बढ़ रहे थे। और तब उस समय, उसके पीछे थे डॉ. मनमोहन सिंह। मुझे सन् 2004 की धूंधली यादें हैं जब सुषमा स्वराज ने एक बड़ा तमाशा किया था। उन्होंने धरमकी दी थी कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वे अपना सिर मुँडवा कर सन्यासिन बन जाएंगी। मुझे यह भी याद है कि किस तरह सोनिया गांधी ने विषय के भारी शोर-शराबे के बीच यह सिद्ध किया था कि उनका कद उन सबसे ऊँचा है। उन्होंने साफ़ कहा कि वे प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहतीं और यह जिम्मेदारी उन्होंने डॉ. मनमोहन सिंह को सौंपने की घोषणा भी की। इस एक्सीडेंटल प्राईम मिनिस्टर ने उसी दिन कहा था कि हम भविष्य को खुशियों से भर देंगे और यही हुआ भी। प्रधानमंत्री बतारै वे भारत को सचमुच एक खुशावा नर भविष्य का जार ले गए। दुनिया में तब भारत पर विश्वास था। सन् 1991 में उन्होंने जो बीज बोए थे उनकी फसल काटने का वक्त आ चुका था। सन् 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री बतारै अपने कार्यकाल में उन्होंने भारत को आधुनिकता और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ाया। उसे पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनाने में भी योगदान दिया। उनके कार्यकाल में अर्थव्यवस्था नौ प्रतिशत की गति से बढ़ी। इतना ही नहीं भारत को लंबे समय बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रुतबा हासिल हुआ। उन्होंने अमेरिका के साथ ऐतिहासिक परमाणु संधि की। आईटी सेवाओं के नियांत के कारण देश में ढेर सरे डालर आ रहे थे। 1991 के मध्य में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब एक अरब डालर का था। उनके कार्यकाल की समाप्ति के समय इस भंडार में 280 अरब डालर थे और अब उसके करीब दो गुना हैं। भारत शाईन कर रहा था और भारतीयों के चेहरों पर भी चमक थी - भारत में भी और विदेश में भी। हमारे साथ कहीं दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार नहीं होता था। हमें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। देश जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा था उसे भी दुनिया प्रशंसा की निगाह से देख रही थी। हम चौन से मुकाबिल थे और विकासित देशों के कलब की सदस्यता हासिल करने की ओर बढ़ रहे थे। अर्थक मामलों की डॉ मनमोहन सिंह की समझ और उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें पूरी दुनिया में समान का पात्र बनाया था। देश में एक तरह का चैन और सुकून था। सबको पता था कि शीर्ष पर बैठा आदमी समाज को बांटने वाला नहीं है।

भारतीय संस्कृति का समेकित जयघोष है-प्रयागराज महापर्व महाकुंभ 2025

विश्व का सबसे बड़ा सनातन धर्म मेला कुंभमेला 2025 का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक होने जा रहा है।



 सनातनी परंपरा का यह पड़ाव बारह वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद धर्मालूओं को मिलने जा रहा है। भारतीयों को ही नहीं अपितु विदेशियों को भी अपनी भव्यता और आध्यात्मिकता के लिए

फ्रट (नदा किनार सान्द्य स्थल) का जन्माण कराया गया है। प्रारंभिक आकलन के मुताबिक महाकुंभ में देश-विदेश के करीब पैंतलीस करोड़ आस्थावान आगंतुकों के शामिल होने की संभावना व्यक्त की गई है। यह एक विश्व कीर्तिमान होगा। यहां आने वाले सभी धर्मात्माओं को जी पी एस युक डिजिटल रिस्ट बैंड देने की व्यवस्था की गई है, जिससे व्यक्ति विशेष के गुम हो जाने अथवा अन्य अप्रत्याशित घटना - दुर्घटना की स्थिति में लोकेशन की जानकारी हो सकेगी। इसके अलावा इंटरिप्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर को अपग्रेड किया गया है। इससे भीड़ प्रबंधन में सहायता मिलेगी। सी सी टी वी कैमरों को देखने के लिए बावन सीटर चार व्यूंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। महाकुंभ की वेबसाइट, ऐप, 11 भाषाओं में एआई चैट बॉट, बहुभाषीय डिजिटल खोया-पाया केंद्र, ड्रोन आधारित निगरानी एवं अपदान

प्रबंधन, आद का चाकचाबद व्यवस्था का गई ह  
मेले की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाय  
जा सकता है कि लगभग 4000 हेक्टर भूक्षेत्र का  
मेला स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जं  
की पूर्व के वर्षों में 3200 हेक्टर होता था  
श्रद्धालुओं के आवास हेतु दो हजार से अधिक  
विशालकाय तंबुनुमा टेंट सिटी बनाए गए हैं। समस्त  
क्षेत्रों की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सिंगल यूज  
प्लास्टिक पर पूरी तरह से पार्बंदी रखी गई है। खान-  
पान के लिए दोनों पत्तल का उपयोग सुनिश्चित किया  
गया है। कुंभ स्थल की सफर्झ हेतु दस लाख सफर्झ  
कर्मी सेवारत रहेंगे। स्वच्छता के साथ ही  
सुरक्षा, पार्किंग, प्रकाश और स्वास्थ्य सुविधाओं का  
बहुद विस्तार किया गया है। यातायात आवागमन के  
सुविधाजनक बनाने हेतु बड़े-बड़े खोखले कंटेनरों से  
पानी पर तैरता हुआ चलित सेतु पॉटून पुलों क

निर्माण किया गया है। कुंभ स्थल में साठ हजार से अधिक सड़क बत्ती से पूर्णिमा सदृश्य रोशन करने की तैयारी की गई है। श्रद्धालुओं के भीतर सौंदर्य बोध और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने की दृष्टि से दीवारों पर भारतीय सभ्यता संस्कृति पर केंद्रित चित्ताकर्षक चित्रकारी, इंद्रधनुषी लाइटिंग की गई है। प्रयागराज के नैनी स्थित अरैल तट पर कुंभ की आध्यात्मिकता को और अधिक समृद्ध करने के लिए शिवालय पार्क का निर्माण भारत के मानचित्र के आकार में किया जा रहा है। लगभग 11 एकड़ में फैले पार्क में 12 ज्योतिलिंगों, नेपाल के शिवालय सहित देश के अन्य प्रमुख मंदिरों के प्रतिरूपों को दर्शनार्थी देख सकेंगे। पार्क की खासियत यह है कि इसका निर्माण वेस्ट मट्रियल से किया जा रहा है, जो कि पर्यावरण के अनुकूल रहेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को महाकुंभ में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आमंत्रित किया है। उनकी ओर से आमंत्रण पत्र लेकर आए उत्तर प्रदेश के मंत्री द्वय सुनील शर्मा और संजय गोंड 10 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री से मिले और आमंत्रण पत्र, गंगाजल तथा कुंभ का प्रतीक चिन्ह उठें भेट किये। इस अवसर पर सीएस साय ने कुंभ स्थल पर छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं हेतु ठहरने खान- पान प्रबंध समुचित बनाए रखने जोर दिया। विदित हो कि कुंभ जाने आने के लिए छत्तीसगढ़ से तीन स्पेशल ट्रेन की सुविधा रेलवे बोर्ड द्वारा प्रदान की गई है।

विजय मिश्रा आमत  
वरिष्ठ लोक हिंदी रंगकर्मी  
अग्रोहा कालोनी रायपुर (छग )  
मो9893123310







